भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1919
बुधवार, 11 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप

1919. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कार्यरत अंतरिक्ष स्टार्टअप की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 से पहले देश में कार्यरत अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या कितनी है और वर्ष 2014 के बाद शुरू किए गए प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्टअप के नाम क्या हैं और नए अंतरिक्ष स्टार्टअप्स का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं, नीतियों और संस्थागत कार्यढांचे का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त योजनाओं/नीतियों के अंतर्गत सरकार के मुख्य लक्षित क्षेत्र, जैसे प्रक्षेपण सेवाएं, उपग्रह निर्माण, संचार, नौवहन या अन्य उभरते क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पहलों के माध्यम से अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

****

(क) और (ख)

पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स की संख्या वर्ष 2014 में केवल 1 से बढ़कर वर्तमान में 400 से अधिक हो गई है। देश में नवाचार को बढ़ावा देना और सहायता, वित्तपोषण तथा आसान विनियामक ढांचे प्रदान करके एक मजबूत स्टार्ट-अप परितंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में घोषणा की गई स्टार्ट-अप इंडिया पहल के बाद, अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्टार्ट-अप्स में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के बाद देश में विकसित प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स में मेसर्स पिक्सेल, मेसर्स ध्रुवा, मेसर्स स्काईरूट एरोस्पेस, मेसर्स अग्निकुल कॉस्मॉस, मेसर्स बेल्लाट्रिक्स एरोस्पेस आदि शामिल हैं।

(ग) अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, नीतियों और संस्थागत कार्यढांचे का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	**योजना / नीति**	**वर्ष**
1.	भारतीय अंतरिक्ष नीति	2023
2.	उदारीकृत एफडीआई नीति	2024
3.	प्राधिकरण के लिए मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं	2024
4.	इन-स्पेस बीज निधि योजना	2023
5.	इन-स्पेस प्री-इनक्यूबेशन उद्यमिता (पीआईई) कार्यक्रम	2024
6.	1000 करोड़ रुपये की उद्यम पूँजी निधि की स्थापना	2024
7.	500 करोड़ रुपये की प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि (टीएएफ) की स्थापना	2025
8.	एचएएल को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	2025
9.	पीपीपी मॉडल पर भू-प्रेक्षण (ईओ) उपग्रह समूह की स्थापना	2026

(घ) सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों, अर्थात् अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम में आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है।

(ङ) अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के साथ प्राप्त की गई उपलब्धियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। तथापि, अब तक प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

i. अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स की संख्या 400 से अधिक हो गई।
ii. अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स में निवेश 500 मिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया।
iii. दो निजी क्षेत्र की कंपनियों ने नवंबर 2022 और मई 2024 में उप-कक्षीय कक्षा में अपने प्रक्षेपण यानों का परीक्षण किया और उड़ान भरी।
iv. पीएसएलवी कक्षीय परीक्षणात्मक मॉड्यूल (पीओईएम) पर कुल 25 नीतभार उड़ान भर चुके हैं/उड़ान भरने वाले हैं, जो एनजीई को उनके नीतभारों की अंतरिक्ष उड़ान योग्यता का परीक्षण करने और योग्यता साबित करने में मदद करते हैं।
v. कुल 6 भारतीय गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) ने 18 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया है।
vi. पीपीपी मॉडल पर भू-प्रेक्षण (ईओ) उपग्रह समूह की स्थापना का ठेका देने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हमारी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों का वैश्विक स्तर पर विश्वास बढ़ेगा।
vii. एसएसएलवी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ प्रक्षेपण यानों की उच्चतर थ्रूपुट क्षमता।
viii. 25 ऐसी कंपनियां हैं जो पीओईएम जैसे मंचों का लाभ उठाकर अंतरिक्ष के वास्तविक वातावरण में पहले से अपने उपग्रहों/उपप्रणालियों का परीक्षण कर रही हैं।
ix. राज्य सरकार अंतरिक्ष को एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में देख रही है और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय नीतियां बना रही है।
x. भारतीय अंतरिक्ष कंपनियां धीरे-धीरे वैश्विक एयरोस्पेस और अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी जगह बना रही हैं।

****